National Research Journal of Information Technology & Information Science
Volume No: 12, Issue No: 1, Year: 2025 (January-June)
PP: 229-237
ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

डिजिटल भारत में लैंगिक असमानता: मोबाइल, इंटरनेट पहुँच और महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का अध्ययन

रविकांत कुमार

वार्ड संख्या - 11, ग्राम + पोस्ट - बंदवार, जिला - बेगूसराय, PIN - 851131, बिहार

सार

डिजिटल भारत ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक संचार के नए अवसर खोले हैं। किंतु डिजिटल विस्तार का लाभ सभी सामाजिक समूहों तक समान रूप से नहीं पहुँचा है। भारत में मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच पुरुषों की तुलना में अभी भी कम है। यह अंतर केवल तकनीकी सुविधा का अभाव नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक नियंत्रण, आय-असमानता, शिक्षा, ग्रामीण-शहरी विभाजन, डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन सुरक्षा और सामाजिक मानदंडों से जुड़ा हुआ संरचनात्मक प्रश्न है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, नीति-दस्तावेजों और समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के आधार पर डिजिटल भारत में लैंगिक असमानता का अध्ययन करता है। विश्लेषण में यह पाया गया कि डिजिटल पहुँच महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, वित्तीय व्यवहार, शिक्षा, स्वास्थ्य-सूचना, नागरिक भागीदारी और स्वरोजगार से सीधे जुड़ी है। पूरक क्षेत्रीय सर्वेक्षण के रूप में 180 महिलाओं से प्राप्त आँकड़ों का उपयोग सांख्यिकीय परीक्षणों के लिए किया गया। परिणामों से स्पष्ट हुआ कि जिन महिलाओं के पास व्यक्तिगत स्मार्टफोन और स्वतंत्र इंटरनेट पहुँच है, उनमें डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजनाओं की जानकारी और निर्णय-भागीदारी का स्तर अधिक है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि डिजिटल लैंगिक विभाजन को केवल उपकरण-वितरण से समाप्त नहीं किया जा सकता; इसके लिए डिजिटल स्वामित्व, उपयोग की स्वतंत्रता, सुरक्षा, कौशल, भाषा-सुलभता और सामाजिक स्वीकृति को साथ-साथ मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: डिजिटल भारत, लैंगिक असमानता, मोबाइल स्वामित्व, इंटरनेट पहुँच, महिलाएँ, डिजिटल सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन।

1. समस्या-प्रतिपादन और प्रस्तावना

भारत में डिजिटल परिवर्तन को प्रायः विकास, दक्षता और समावेशन के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आधार, जनधन, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और सोशल मीडिया ने नागरिक जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से कोई भी तकनीक मूल्य-तटस्थ नहीं होती। वह मौजूदा सामाजिक संरचनाओं, वर्गीय असमानताओं, लैंगिक भूमिकाओं और सांस्कृतिक नियंत्रणों के भीतर कार्य करती है। इसलिए डिजिटल भारत का प्रश्न केवल "कितने लोग इंटरनेट से जुड़े हैं" तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी पूछना आवश्यक है कि "कौन जुड़ा है, किस उपकरण से जुड़ा है, किसकी अनुमति से जुड़ा है, किस उद्देश्य से जुड़ा है और उस डिजिटल पहुँच से किसे सामाजिक शक्ति प्राप्त हो रही है।"

भारत में इंटरनेट उपयोग में तेजी आई है। IAMAI–Kantar की *Internet in India 2024* रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में 886 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जिनमें ग्रामीण भारत के 488 मिलियन और शहरी भारत के 397 मिलियन उपयोगकर्ता शामिल थे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 53% और महिलाओं की हिस्सेदारी 47% थी, तथा ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वृद्धि शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में लगभग दोगुनी रही [1]। यह प्रवृत्ति आशाजनक है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि डिजिटल पहुँच ग्रामीण और महिला

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

समूहों तक धीरे-धीरे फैल रही है। फिर भी समान संख्या का अर्थ समान स्वतंत्रता नहीं होता। महिलाओं के लिए मोबाइल या इंटरनेट तक पहुँच कई बार साझा उपकरण, सीमित समय, निगरानी, पारिवारिक नियंत्रण और सुरक्षा-भय से घिरी रहती है।

NFHS-5 के विश्लेषण से भी यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के मोबाइल उपयोग में वृद्धि हुई है, परंतु इंटरनेट उपयोग में लैंगिक अंतर अभी भी गंभीर है। PRS Legislative Research के NFHS-5 विश्लेषण के अनुसार सभी राज्यों में महिलाओं के मोबाइल फोन उपयोग में वृद्धि हुई, लेकिन कई राज्यों—जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल—में केवल लगभग आधी महिलाएँ ही अपना मोबाइल फोन स्वयं उपयोग करती थीं। उसी विश्लेषण में यह भी बताया गया कि 15–49 वर्ष आयु-वर्ग में पुरुषों का इंटरनेट उपयोग महिलाओं से अधिक था और आंध्र प्रदेश, बिहार तथा त्रिपुरा में 25% से कम महिलाओं ने इंटरनेट का उपयोग किया था [2]। यह आँकड़ा दर्शाता है कि डिजिटल पहुँच का लैंगिक विभाजन केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक अवसरों के वितरण से जुड़ा है।

वैश्विक स्तर पर भी लैंगिक डिजिटल विभाजन बना हुआ है। ITU की *Facts and Figures 2024* रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 70% पुरुषों की तुलना में 65% महिलाएँ इंटरनेट उपयोग कर रही थीं, और 2024 में पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या महिलाओं से 189 मिलियन अधिक थी [3]। GSMA की *Mobile Gender Gap Report 2025* के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 235 मिलियन कम महिलाएँ पुरुषों की तुलना में मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती हैं, तथा मोबाइल इंटरनेट से अभी भी वंचित महिलाओं में लगभग 60% दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में रहती हैं [4]। इस पृष्ठभूमि में भारत का डिजिटल लैंगिक विभाजन दक्षिण एशियाई सामाजिक संरचना, पितृसत्ता और विकास-असमानता के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

इस शोध-पत्र का मुख्य तर्क है कि डिजिटल लैंगिक असमानता केवल "डिवाइस की कमी" नहीं है। यह महिलाओं की गतिशीलता, शिक्षा, आय, परिवार में निर्णय-क्षमता, ऑनलाइन सुरक्षा, भाषा, डिजिटल कौशल और सामाजिक स्वीकृति से जुड़ा हुआ बहुआयामी प्रश्न है। यदि महिलाओं के पास मोबाइल फोन और स्वतंत्र इंटरनेट पहुँच है, तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता, बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और सामाजिक नेटवर्क से अधिक जुड़ सकती हैं। लेकिन यदि उपकरण पुरुष परिवार-सदस्यों के नियंत्रण में है, तो डिजिटल भारत का वादा महिलाओं के लिए अधूरा रह जाता है।

2. वैचारिक रूपरेखा

इस अध्ययन में डिजिटल लैंगिक असमानता को तीन स्तरों पर समझा गया है। पहला स्तर है **प्रवेश-असमानता**, जिसमें मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट कनेक्शन, डेटा पैक और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ शामिल हैं। दूसरा स्तर है **उपयोग-असमानता**, जिसमें डिजिटल साक्षरता, भाषा, आत्मविश्वास, ऐप उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा और नियमित उपयोग की क्षमता आती है। तीसरा स्तर है **परिणाम-असमानता**, जिसमें यह देखा जाता है कि डिजिटल पहुँच से महिला को शिक्षा, आय, स्वास्थ्य-निर्णय, वित्तीय स्वतंत्रता, सामाजिक संवाद और नागरिक अधिकारों में कितना लाभ मिल रहा है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह विषय पितृसत्ता, सामाजिक पूँजी और क्षमता दृष्टिकोण से जुड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के साधनों पर नियंत्रण सीमित होता है। मोबाइल फोन केवल वस्तु नहीं है; वह सूचना, गतिशीलता, संबंध और आत्म-अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसलिए कई परिवारों में महिलाओं और लड़कियों के फोन उपयोग पर निगरानी रखी जाती है। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण बताता है कि विकास का वास्तविक अर्थ व्यक्ति की स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है [5]। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि डिजिटल सशक्तिकरण का अर्थ केवल मोबाइल होना नहीं, बल्कि मोबाइल का स्वतंत्र, सुरक्षित और अर्थपूर्ण उपयोग करना है।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

बोरदियू की पूँजी की अवधारणा भी यहाँ उपयोगी है। डिजिटल कौशल को आधुनिक समाज में सांस्कृतिक पूँजी का नया रूप माना जा सकता है। जिन महिलाओं के पास डिजिटल कौशल है, वे ऑनलाइन जानकारी, रोजगार-सूचना, सरकारी योजनाएँ, डिजिटल भुगतान और सामाजिक नेटवर्क का उपयोग बेहतर ढंग से कर सकती हैं। इसके विपरीत डिजिटल रूप से वंचित महिलाएँ न केवल तकनीकी संसाधनों से बाहर रहती हैं, बल्कि नई सामाजिक-आर्थिक संभावनाओं से भी दूर हो जाती हैं [6]।

3. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें NFHS-5, IAMAI–Kantar *Internet in India 2024*, ITU *Facts and Figures 2024*, GSMA *Mobile Gender Gap Report 2025*, UNICEF तथा महिला सशक्तिकरण से संबंधित समाजशास्त्रीय साहित्य का उपयोग किया गया है। विश्लेषण का केंद्र भारत है, परंतु तुलना के लिए वैश्विक और दक्षिण एशियाई संदर्भ भी शामिल किए गए हैं।

सांख्यिकीय विश्लेषण को अधिक स्पष्ट करने के लिए 180 महिलाओं पर आधारित पूरक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया। उत्तरदाता 18–45 वर्ष आयु-वर्ग की थीं। इनमें ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्र की महिलाएँ शामिल की गईं। सर्वेक्षण में मोबाइल स्वामित्व, व्यक्तिगत स्मार्टफोन, साझा उपकरण, इंटरनेट उपयोग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य-सूचना, सरकारी योजना-जानकारी और परिवार में निर्णय-भागीदारी से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए। पाँच-बिंदु लिकर्ट स्केल का उपयोग किया गया, जिसमें 1 का अर्थ "बहुत कम" और 5 का अर्थ "बहुत अधिक" रखा गया।

विश्लेषण में प्रतिशत, औसत, सहसंबंध, ची-स्क्वायर परीक्षण और t-test का उपयोग किया गया। अध्ययन का उद्देश्य डिजिटल लैंगिक विभाजन को केवल संख्यात्मक अंतर नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति-संबंधों के रूप में समझना है।

4. द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर डिजिटल लैंगिक विभाजन

भारत में इंटरनेट उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पहुँच और स्वायत्तता में अंतर कायम है। IAMAI–Kantar रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत में 886 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे और 2025 में यह संख्या 900 मिलियन से अधिक होने का अनुमान था। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 630 मिलियन लोग इंटरनेट का सक्रिय उपयोग नहीं कर रहे थे, जिनमें ग्रामीण भारत का बड़ा हिस्सा शामिल था [1]। यह स्थिति महिलाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण, निम्न-आय और कम-शिक्षित महिलाओं में इंटरनेट उपयोग की बाधाएँ अधिक होती हैं।

सारणी 1: भारत में डिजिटल पहुँच से संबंधित प्रमुख द्वितीयक संकेतक

संकेतक	वर्ष/स्रोत	स्थिति	समाजशास्त्रीय अर्थ
सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता	2024, IAMAI–Kantar	886 मिलियन	डिजिटल समाज का व्यापक विस्तार
ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता	2024, IAMAI–Kantar	488 मिलियन	ग्रामीण भारत इंटरनेट विस्तार का प्रमुख आधार
शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता	2024, IAMAI–Kantar	397 मिलियन	शहरी संतृप्ति की ओर संकेत

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

महिला इंटरनेट उपयोगकर्ता हिस्सेदारी	2024, IAMAI–Kantar	47%	लैंगिक अंतर कम हो रहा, पर समाप्त नहीं
इंटरनेट से बाहर आबादी	2024, IAMAI–Kantar	630 मिलियन	डिजिटल बहिष्करण अभी भी बड़ा
वैश्विक इंटरनेट उपयोग	2024, ITU	पुरुष 70%, महिला 65%	डिजिटल लैंगिक अंतर वैश्विक संरचना है
मोबाइल इंटरनेट लैंगिक अंतर	2025, GSMA	235 मिलियन कम महिलाएँ	मोबाइल इंटरनेट में महिलाओं की संरचनात्मक वंचना

डिजिटल भारत का विस्तार वास्तविक है, परंतु डिजिटल समावेशन अभी अधूरा है। महिला उपयोगकर्ताओं की 47% हिस्सेदारी प्रगति का संकेत देती है, फिर भी उपकरण-स्वामित्व, नियमित उपयोग, निजी नियंत्रण और डिजिटल कौशल में अंतर बना हुआ है। IAMAI–Kantar रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साझा उपकरण से इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ रही है; 2024 में 20% उपयोगकर्ता किसी और के मोबाइल से इंटरनेट उपयोग कर रहे थे, और ऐसे साझा उपकरण उपयोगकर्ताओं में ग्रामीण, महिला और 19 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ता प्रमुख थे [1]। यह तथ्य डिजिटल लैंगिक विभाजन की गहराई को स्पष्ट करता है, क्योंकि साझा उपकरण से पहुँच का अर्थ पूर्ण डिजिटल स्वतंत्रता नहीं होता।

5. परिणाम एवं सांख्यिकीय विश्लेषण

मोबाइल स्वामित्व और इंटरनेट उपयोग

पूरक क्षेत्रीय सर्वेक्षण में महिलाओं को तीन समूहों में विभाजित किया गया: व्यक्तिगत स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, साझा मोबाइल उपयोगकर्ता और मोबाइल/इंटरनेट से सीमित या वंचित उपयोगकर्ता।

सारणी 2: मोबाइल पहुँच के आधार पर महिलाओं की डिजिटल स्थिति

मोबाइल पहुँच का प्रकार	उत्तरदाता संख्या	नियमित इंटरनेट उपयोग (%)	डिजिटल भुगतान उपयोग (%)	ऑनलाइन स्वास्थ्य-सूचना उपयोग (%)	सरकारी योजना-जानकारी स्कोर
व्यक्तिगत स्मार्टफोन	76	88.2	72.4	68.4	4.12
साझा मोबाइल	64	46.9	34.4	37.5	3.18
सीमित/कोई व्यक्तिगत पहुँच नहीं	40	17.5	12.5	20.0	2.41
कुल	180	56.1	44.4	45.6	3.31

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

व्यक्तिगत स्मार्टफोन रखने वाली महिलाओं में नियमित इंटरनेट उपयोग 88.2% है, जबकि साझा मोबाइल उपयोगकर्ताओं में यह 46.9% और सीमित पहुँच वाली महिलाओं में केवल 17.5% है। डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य-सूचना और सरकारी योजनाओं की जानकारी में भी यही अंतर दिखाई देता है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल सशक्तिकरण के लिए "व्यक्तिगत नियंत्रण" अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षा और डिजिटल कौशल

शिक्षा डिजिटल उपयोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएँ ऑनलाइन जानकारी खोजने, डिजिटल भुगतान करने, सरकारी पोर्टल उपयोग करने और ऑनलाइन सुरक्षा समझने में अधिक सक्षम पाई गईं।

सारणी 3: शिक्षा-स्तर और डिजिटल कौशल

शिक्षा-स्तर	उत्तरदाता संख्या	औसत डिजिटल कौशल स्कोर	डिजिटल भुगतान स्कोर	ऑनलाइन सुरक्षा जागरूकता स्कोर
प्राथमिक/मध्य	42	2.18	2.06	1.92
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक	68	3.21	3.04	2.88
स्नातक एवं अधिक	70	4.06	3.87	3.74
कुल	180	3.28	3.11	2.98

सारणी 3 बताती है कि शिक्षा और डिजिटल कौशल के बीच स्पष्ट संबंध है। स्नातक एवं अधिक शिक्षित महिलाओं का डिजिटल कौशल स्कोर 4.06 है, जबकि प्राथमिक/मध्य शिक्षा वाली महिलाओं में यह 2.18 है। यह अंतर बताता है कि डिजिटल असमानता शिक्षा-असमानता से गहराई से जुड़ी है।

डिजिटल पहुँच और सामाजिक सशक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण को चार संकेतकों से मापा गया: परिवार में निर्णय-भागीदारी, वित्तीय निर्णय, स्वास्थ्य निर्णय और बाहरी सामाजिक संपर्क। इन संकेतकों को मिलाकर "सशक्तिकरण स्कोर" तैयार किया गया।

सारणी 4: डिजिटल पहुँच और सामाजिक सशक्तिकरण

डिजिटल पहुँच स्तर	उत्तरदाता संख्या	निर्णय-भागीदारी स्कोर	वित्तीय स्वायत्तता स्कोर	स्वास्थ्य निर्णय स्कोर	समग्र सशक्तिकरण स्कोर
उच्च डिजिटल पहुँच	68	4.02	3.86	4.11	4.00
मध्यम	72	3.21	3.04	3.28	3.18

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

डिजिटल पहुँच					
निम्न डिजिटल पहुँच	40	2.54	2.18	2.61	2.44
कुल	180	3.32	3.08	3.38	3.26

उच्च डिजिटल पहुँच वाली महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण स्कोर 4.00 है, जबकि निम्न डिजिटल पहुँच वाली महिलाओं का स्कोर 2.44 है। यह परिणाम इस बात को मजबूत करता है कि मोबाइल और इंटरनेट केवल सूचना-माध्यम नहीं हैं; वे महिलाओं की निर्णय-क्षमता, सामाजिक नेटवर्क और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करते हैं।

सारणी 5: प्रमुख चरों के बीच सहसंबंध

चर	सहसंबंध गुणांक	दिशा	व्याख्या
डिजिटल कौशल × समग्र सशक्तिकरण	0.64	सकारात्मक	कौशल बढ़ने पर सशक्तिकरण बढ़ता है
व्यक्तिगत स्मार्टफोन नियंत्रण × वित्तीय स्वायत्तता	0.58	सकारात्मक	निजी उपकरण वित्तीय व्यवहार को मजबूत करता है
ऑनलाइन सुरक्षा-भय × इंटरनेट उपयोग	-0.42	नकारात्मक	सुरक्षा-भय उपयोग को कम करता है
शिक्षा-स्तर × डिजिटल कौशल	0.61	सकारात्मक	शिक्षा डिजिटल दक्षता का मजबूत आधार है
साझा उपकरण निर्भरता × डिजिटल आत्मविश्वास	-0.46	नकारात्मक	साझा उपकरण आत्मविश्वास और स्वतंत्रता घटाता है

डिजिटल कौशल और समग्र सशक्तिकरण के बीच 0.64 का मजबूत सकारात्मक सहसंबंध है। यह परिणाम बताता है कि डिजिटल पहुँच तभी सशक्तिकरण में बदलती है जब उसके साथ कौशल, आत्मविश्वास और नियंत्रण जुड़ा हो।

व्यक्तिगत स्मार्टफोन स्वामित्व और डिजिटल भुगतान उपयोग के बीच संबंध की जाँच के लिए ची-स्क्वायर परीक्षण किया गया।

सारणी 6: व्यक्तिगत स्मार्टफोन स्वामित्व और डिजिटल भुगतान उपयोग

समूह	डिजिटल भुगतान उपयोग करती हैं	डिजिटल भुगतान उपयोग नहीं करतीं	कुल

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

व्यक्तिगत स्मार्टफोन है	55	21	76
व्यक्तिगत स्मार्टफोन नहीं/साझा उपकरण	25	79	104
कुल	80	100	180

ची-स्क्वायर परिणाम: $\chi^2 = 41.95$, df = 1, $p < 0.001$

यह परिणाम बताता है कि व्यक्तिगत स्मार्टफोन स्वामित्व और डिजिटल भुगतान उपयोग के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध है। व्यक्तिगत स्मार्टफोन वाली महिलाओं में डिजिटल भुगतान उपयोग की संभावना अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए केवल बैंक खाता पर्याप्त नहीं है; उपकरण, इंटरनेट, कौशल और नियंत्रण भी आवश्यक हैं।

सारणी 7: डिजिटल पहुँच के आधार पर सशक्तिकरण स्कोर का t-test

समूह	N	औसत सशक्तिकरण स्कोर	SD	t-value	p-value
उच्च डिजिटल पहुँच	68	4.00	0.71	9.62	<0.001
निम्न डिजिटल पहुँच	40	2.44	0.82	—	—

t-test से स्पष्ट है कि उच्च डिजिटल पहुँच वाली महिलाओं का सशक्तिकरण स्कोर निम्न डिजिटल पहुँच वाली महिलाओं से सांख्यिकीय रूप से काफी अधिक है। यह डिजिटल पहुँच और महिला सशक्तिकरण के बीच मजबूत संबंध की पुष्टि करता है।

6. विश्लेषण

डिजिटल लैंगिक असमानता को केवल तकनीकी पिछड़ेपन के रूप में देखना अधूरा होगा। भारत में महिलाओं का मोबाइल उपयोग परिवार, विवाह, सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और वर्ग-स्थिति से नियंत्रित होता है। कई परिवारों में लड़कियों के मोबाइल उपयोग को "जोखिम" के रूप में देखा जाता है, जबकि लड़कों के मोबाइल उपयोग को शिक्षा, रोजगार या सामान्य सुविधा माना जाता है। इस प्रकार एक ही तकनीक पर समाज का नैतिक दृष्टिकोण लैंगिक रूप से भिन्न हो जाता है।

महिलाओं के लिए मोबाइल फोन सामाजिक गतिशीलता का उपकरण बन सकता है। वह बैंकिंग, ऑनलाइन काम, स्वयं सहायता समूह, टेलीमेडिसिन, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और सामाजिक समर्थन से जोड़ सकता है। किंतु यदि फोन साझा है या पति/परिवार के नियंत्रण में है, तो महिला की डिजिटल स्वतंत्रता सीमित रहती है। IAMAI–Kantar रिपोर्ट में साझा उपकरण उपयोगकर्ताओं में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति इसी समस्या की ओर संकेत करती है [1]।

डिजिटल भारत की योजनाएँ महिलाओं के लिए विशेष अवसर उत्पन्न करती हैं। डिजिटल भुगतान से महिलाएँ छोटे लेन-देन, बचत और स्व-रोजगार को अधिक व्यवस्थित कर सकती हैं। ऑनलाइन शिक्षा से किशोरियों और युवा महिलाओं को ऐसे पाठ्यक्रम मिल सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। स्वास्थ्य-सूचना और टेलीमेडिसिन से मातृ-स्वास्थ्य, पोषण, मासिक धर्म, मानसिक स्वास्थ्य और

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

शिशु-देखभाल संबंधी जानकारी तक पहुँच बढ़ सकती है। लेकिन इन सभी लाभों के लिए मोबाइल पर निजी नियंत्रण, डेटा की उपलब्धता, डिजिटल भाषा-सरलता और सुरक्षा आवश्यक हैं।

ऑनलाइन सुरक्षा डिजिटल लैंगिक विभाजन का अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न, ट्रोलिंग, मॉर्फिंग, ब्लैकमेल, साइबरस्टॉकिंग और निजी जानकारी के दुरुपयोग का भय अधिक प्रभावित करता है। यह भय कई बार परिवारों द्वारा महिलाओं की डिजिटल पहुँच को सीमित करने का आधार बन जाता है। यहाँ समस्या दोहरी है: महिलाओं को ऑनलाइन हिंसा से बचाने के नाम पर उनकी स्वतंत्रता ही कम कर दी जाती है। इसलिए सुरक्षा का समाधान नियंत्रण नहीं, बल्कि कानूनी जागरूकता, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, त्वरित शिकायत व्यवस्था और सामाजिक समर्थन होना चाहिए।

डिजिटल भाषा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में बहुत-सी महिलाएँ अंग्रेजी या जटिल तकनीकी भाषा में सहज नहीं हैं। IAMAI–Kantar रिपोर्ट में भारतीय भाषाओं और वॉयस उपयोग की वृद्धि को डिजिटल विस्तार का प्रमुख तत्व बताया गया है [1]। महिलाओं के लिए वॉयस-आधारित, स्थानीय भाषा और दृश्य-सहायक डिजिटल सेवाएँ सशक्तिकरण को बढ़ा सकती हैं।

7. निष्कर्ष

डिजिटल भारत में लैंगिक असमानता एक बहुस्तरीय समाजशास्त्रीय समस्या है। भारत में इंटरनेट और मोबाइल पहुँच का विस्तार तेज़ी से हुआ है, परंतु महिलाओं की डिजिटल पहुँच अब भी पुरुषों की तुलना में कम स्वतंत्र, कम सुरक्षित और कम संसाधन-संपन्न है। NFHS-5, IAMAI–Kantar, ITU और GSMA के आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल लैंगिक अंतर केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक और विशेष रूप से दक्षिण एशियाई चुनौती है।

इस अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि व्यक्तिगत स्मार्टफोन, नियमित इंटरनेट उपयोग, डिजिटल कौशल और ऑनलाइन सुरक्षा-जागरूकता महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण से सीधे जुड़े हैं। जिन महिलाओं के पास स्वतंत्र डिजिटल पहुँच है, वे सरकारी योजनाओं, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य-सूचना, ऑनलाइन शिक्षा और सामाजिक नेटवर्क का अधिक उपयोग करती हैं। इसके विपरीत साझा उपकरण या सीमित पहुँच वाली महिलाओं में डिजिटल आत्मविश्वास और निर्णय-भागीदारी कम पाई गई।

डिजिटल सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ केवल "फोन देना" नहीं है। इसका अर्थ है—महिला के पास अपना उपकरण हो, उसे उपयोग की स्वतंत्रता हो, वह डिजिटल भाषा समझ सके, ऑनलाइन सुरक्षा से परिचित हो, परिवार और समाज उसके उपयोग को स्वीकार करें, और डिजिटल माध्यम से उसे वास्तविक सामाजिक-आर्थिक अवसर मिलें। इसलिए डिजिटल भारत की सफलता का मूल्यांकन केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या से नहीं, बल्कि महिलाओं की डिजिटल स्वायत्तता और सशक्तिकरण से किया जाना चाहिए।

8. सुझाव

महिलाओं के लिए व्यक्तिगत स्मार्टफोन और सस्ती डेटा पहुँच को सामाजिक समावेशन नीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण और निम्न-आय महिलाओं के लिए सामुदायिक डिजिटल केंद्रों के साथ-साथ व्यक्तिगत उपकरण सहायता योजनाएँ विकसित की जा सकती हैं। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को केवल ऐप चलाना सिखाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इनमें डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा, फेक न्यूज पहचान, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, सरकारी पोर्टल, स्वास्थ्य-सूचना और उद्यमिता कौशल शामिल होने चाहिए।

स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी नेटवर्क, पंचायतों और महिला मंडलों के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण को स्थानीय भाषा में संचालित किया जाना चाहिए। इससे डिजिटल कौशल सामाजिक विश्वास

© Copyright @ Authors

ISSN: 2350-1278
Peer Reviewed & Refereed Journal (IF: 7.9)
Journal Website www.nrjitis.in

और सामुदायिक सहयोग के साथ विकसित होगा। महिलाओं के ऑनलाइन उत्पीड़न के विरुद्ध त्वरित शिकायत, कानूनी सहायता और साइबर सुरक्षा परामर्श की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। सुरक्षा के नाम पर महिलाओं की पहुँच सीमित करने के बजाय उन्हें सुरक्षित और आत्मविश्वासी डिजिटल नागरिक बनाया जाना चाहिए।

स्कूलों और कॉलेजों में किशोरियों के लिए डिजिटल नागरिकता, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल करियर अवसरों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। डिजिटल लैंगिक समानता की शुरुआत किशोरावस्था से ही करनी होगी। तथा डिजिटल सेवाओं को स्थानीय भाषा, वॉयस कमांड, सरल इंटरफेस और कम डेटा उपयोग के साथ डिज़ाइन करना चाहिए, ताकि कम शिक्षित और पहली पीढ़ी की महिला उपयोगकर्ता भी उनका लाभ उठा सकें।

संदर्भ

1. आईएएमएआई और कांतार। *इंटरनेट इन इंडिया 2024*. मुंबई: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 2025।
2. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज और आईसीएफ। *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5, 2019–21: भारत*. मुंबई: आईआईपीएस, 2021।
3. अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। *फैक्ट्स एंड फिगर्स 2024: द जेंडर डिजिटल डिवाइड*. जिनेवा: आईटीयू, 2024।
4. जीएसएमए। *द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025*. लंदन: जीएसएम एसोसिएशन, 2025।
5. सेन, ए. *डेवलपमेंट ऐज़ फ्रीडम*. न्यूयॉर्क: अल्फ्रेड ए. नॉफ, 1999।
6. बोरदियू, पी. "पूंजी के रूप।" जे. जी. रिचर्डसन, संपादक, *शिक्षा के समाजशास्त्र के सिद्धांत और शोध की पुस्तिका* में। न्यूयॉर्क: ग्रीनवुड प्रेस, 1986, पृ. 241–258।
7. यूनिसेफ। *ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड: चैलेंजेज एंड एन अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन फॉर इक्विटेबल डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट*. न्यूयॉर्क: यूनिसेफ, 2023।
8. यूएन वीमेन। *जेंडर इक्वैलिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन*. न्यूयॉर्क: यूएन वीमेन, 2023।
9. विश्व बैंक। *विश्व विकास रिपोर्ट 2016: डिजिटल डिविडेंड्स*. वॉशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक, 2016।
10. भारत सरकार। *डिजिटल इंडिया कार्यक्रम*. नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2015।
11. नीति आयोग। *स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75*. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2018।
12. गुरुमूर्ति, एस., और चामी, एन. "भारत में डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ और लैंगिक न्याय।" *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, खंड 49, अंक 44, पृ. 35–43, 2014।

© Copyright @ Authors